प्रकाशन तिथि–15 फरवरी, 2013

‘अप्प दीपो भव’

वॉयस ऑफ बुद्धा

DL(ND)-11/6144/2013-14-15

R.N.I. No. 68180/98

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 6 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 फरवरी, 2013

मादक पदार्थों से दूर रहें

-गौतम बुद्ध

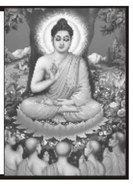

निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए दलित-आदिवासी छात्रों की पुकार

हर्षवर्धन दवणे

फुले–आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ‘फासा’ की ओर से महाराष्ट्र के नांदेड में छात्रों का दलित–आदिवासी सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के मुख्य मार्गदर्शक डॉ. उदित राज (राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ), सम्मेलन के उद्घाटक विद्रोही कवि ‘गदर’ (हैदराबाद) और अध्यक्ष प्रा. डॉ. इंदिरा अठावले थे।

‘‘निजी क्षेत्र में आरक्षण’ दलित, आदिवासी छात्रों के भविष्य के लिए जीवन–मरण से भी भयानक संघर्ष है, यहां दलित छात्रों के माता–पिता अपने खून–पसीने की कमाई अपने बच्चों के पढ़ाई में सिर्फ उनके उज्जवल भविष्य की आशा में लगा रहे हैं। मगर आज दलित–आदिवासी छात्रों का भविष्य निजीकरण के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। ‘निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं तो दलित आदिवासी छात्रों की पढ़ाई है बेकार’’ नारा देकर उदित राज जी ने कहा कि अमेरिका जैसा पूंजीवादी राष्ट्र अपने देश के शोषित अश्वेत लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण एफरमेटिव एक्शन्स के माध्यम से देता है, तो वहीं इस देश में निजी क्षेत्र में दलित, आदिवासियों का शोषण हो रहा है। सरकार को निजी क्षेत्र में भी दलित,आदिवासी छात्रों को आरक्षण देना होगा। पिछले दस साल से परिसंघ छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है, मगर अब छात्रों को अपने भविष्य एवं अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है। आगामी कुछ महीनों में देश के लाखों दलित–आदिवासी छात्रों को संगठित कर राष्ट्रीय छात्र संघ खड़ा किया जाएगा। आगामी दिसंबर तक उपरोक्त मांग को लेकर दिल्ली में रैली करने का निर्णय छात्रों की सर्वसम्मति से लिया गया।

इस छात्र सम्मेलन में विद्रोही कवि गदर (हैदराबाद) ने अपनी बात कविता और गीतों के माध्यम से रखते हुए कहा कि इस देश में आरक्षण सदियों से रहा है और इस आरक्षण से ही सवर्णों ने दलित, आदिवासियों को अछूत बनाये रखा। गंदे धंधे तथा व्यवसाय दिये और उन्हें गुलाम बनाये रखा। मगर बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से शिक्षा, सरकारी नौकरियों में उपलब्धि तथा राजनीति में आरक्षण देकर यह गुलामी तोड़ दी। मगर इस देश की सवर्ण पूंजीपति संवैधानिक आरक्षण को निजी कारणों से खत्म करके फिर से गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके खिलाफ दलित–आदिवासी छात्र तथा युवा संघ संगठित होकर निजी क्षेत्र में अपनी भागीदारी मांगे, इसलिए छात्रों को बड़ा आंदोलन खड़ा करना अब जरूरी है, नहीं तो भविष्य में गुलामी निश्चित है। इस तरह गदर ने छात्रों को अपने गीतों से प्रोत्साहित किया।

इस सम्मेलन के छात्र नेता हर्षवर्धन दवणे ने अपने छात्र मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हम शिक्षा के अधिकार, छात्रवृत्ति तथा छात्रावास के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब हमें हमारे रोजगार के विषय में गंभीर होना पड़ेगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण के बिना भविष्य में रोजगार नहीं मिले तो पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी। इस देश में हजारों सालों से दलित आदिवासियों को अधिकार देने का प्रयास किया गया मगर सवर्णों ने हमारी भागीदारी का विरोध करके गुलामी का समर्थन करते हुए सरकारी क्षेत्र में आरक्षण को भी खत्म करता जा रहा है। लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा। दलित–आदिवासी छात्रों को अपनी भागीदारी मिलना ही चाहिए।

‘निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं तो दलित–आदिवासी छात्रों की पढ़ाई है बेकार’’

-डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

सेना, न्यायपालिका, फिल्म, हर एक निजी क्षेत्र में हमें आरक्षण देना होगा, नहीं तो हजारों सालों के शोषण के खिलाफ हम ‘दलितस्तान’ बनायेंगे, हम अपना वतन बनाऐंगे। हर्षवर्धन के इस बात का छात्रों ने जोरदार समर्थन किया।

इस सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ. इंदिरा अठावले ने कहा कि दलित छात्रों का राष्ट्रीय संगठन नहीं है इसलिए उनकी समस्या भी अधिक है। इसलिए विश्वविद्यालयों में उनका शोषण होता है। जाति देखकर अंक दिए जाते हैं। इसके खिलाफ आवाज उठानेवाला दलित–आदिवासियों का राष्ट्रीय संगठन होना जरूरी है।

इस सम्मेलन में नांदेड जिला अध्यक्ष नितिन गायकवाड़, हिंगोली जिलाध्यक्ष माधव पंडित, परभणी जिलाध्यक्ष, निखिल मकरंद सहित साढ़े तीन हजार छात्रों ने हिस्सा लिया। निजी क्षेत्र में आरक्षण, सेना, न्यायपालिका में आरक्षण और छात्रवृत्ति महंगाई के हिसाब से दी जाए। हर जिला तथा तहसीलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को मुफ्त शिक्षा और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों में आरक्षण की मांग को लेकर आने वाले दिनों में आंदोलन खड़ा करने की मांग हाथ उठाकर समर्थन मांगा और सौ प्रतिशत छात्रों ने हाथ उठाकर इस मांग तथा आंदोलन का समर्थन किया।

छात्र सम्मेलन का उद्घाटन महापुरुषों को वंदन करके और आने वाले क्रांतियुग के शुरुआत का प्रतीक मशाल जलाकर किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन बालाजी कोंडामंगल ने किया।

इस कार्यक्रम के लिए राहुल सोनाले, बंडू नरवाडे, रवि वाघमारे, मनोज जामनोर, नागोराव भाग्यवंत, विशाल कांबले, रहुल सोनकांबले, साहेबराव नरवाडे, धम्मा वाढ़वे, संभाजी गायकवाड, संदीप कौठेकर, अतुल वच्छेवार, तुकाराम पंदिलवाड, सुमेध चिंचलवाड, नागेश सोनुले का सहयोग सराहनीय रहा।

गदर, डॉ. उदित राज (बीच में), इंदिरा अठवले का स्वागत करते लोग

सम्मेलन में उपस्थित अपार भीड़ का दृश्य

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का परिपत्र संख्या-77 साधारण डाक द्वारा परिसंघ के सभी पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है। इसे ज्यों का त्यों छापा जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि अन्य लोगों को भी इसे पढ़ायें और यथासंभव संबंधित लोगों को फोटोकॉपी करवाकर वितरित करें।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
All India Confederation of SC/ST Organisations

Dr. Udit Raj
National Chairman

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Tel: 011-23354841, 011-23354842, Fax: 011-23354842
Email: dr.uditraj@gmail.com, web.: www.scstconfederation.org

परिपत्र संख्या : 77 दिनांक : 09/02/2013

प्रिय

26 नवंबर की रैली के बाद यह पहला परिपत्र है और बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। 18 दिसंबर को पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक राज्य सभा में पास हुआ। निश्चित तौर से हमारी रैली का प्रभाव रहा है। जब 19 दिसंबर को लोक सभा में विधेयक पेश हुआ तो समाजवादी पार्टी के दलित समाज के ही दो सांसद बिल को फाड़ दिए। भले ही बिल फाड़ दिया गया था तो सरकार दूसरा बिल पेश कर सकती थी। समाजवादी पार्टी के मात्र 22 सांसद हैं जो संसद को स्थगित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मामूली झड़पों पर चार बार संसद स्थगित हो गयी और 20 दिसंबर के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया। संसद-सत्र को 22 दिसंबर तक चलना था लेकिन 20 को ही स्थगित कर दिया गया, पता नहीं यह जल्दी क्यों थी ?जब एफ.डी.आई. के ऊपर राज्य सभा में वोटिंग होनी थी तो सरकार खतरे में आ गयी थी और उसे बचाने का काम बसपा ने किया था। उस समय हम लोगों ने सुश्री मायावती तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि वे एफ.डी.आई. के पहले 117वें संवैधानिक संशोधन को पास करवा लें, नहीं तो सरकार मामूली कारण पर भी पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित इस विधेयक को पास नहीं करेगी। कौन नहीं जानता कि सरकार ने जो इच्छा शक्ति एफ.डी.आई. को पास कराने में दिखाई, उसकी यदि आधी भी सक्रियता दिखाई होती तो 117वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पास हो गया होता। इसमें हम लोगों की भी कुछ गलती है कि राष्ट्रीय रैली तक जोर लगाने के बाद वर्ष भर शिथिल रहते हैं। कहां तो हमारी लड़ाई तमाम क्षेत्रों में भागीदारी एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए शुरू हुई थी लेकिन अब पुराने अधिकार को वापिस लेने के लिए शक्ति लगाना पड़ रहा है। क्या विडंबना है, इस समाज की ?लगता है कि हमें फिर से गुलामी की स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा।

निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई का लाभ नौजवानों एवं छात्रों को मिलना है लेकिन हम उन्हें अपने मिशन से अभी तक जोड़ नहीं सके हैं। हर जिले में अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रावास बने हैं। यदि उन तक भी हमारा संदेश पहुंच जाए तो समाज में आंदोलन खड़ा करना मुश्किल नहीं है। जिस आंदोलन में विद्यार्थी एवं नौजवान शामिल हो जाएं, उसको गति मिलनी ही है। हमारे कर्मचारी-अधिकारी सोसल मीडिया जैसे - कम्प्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक, ट्यूटर, ब्लाग, एस.एम.एस., मिस काल इत्यादि का इस्तेमाल करने में हिचकते हैं, जबकि इसी पीढ़ी के ज्यादातर सवर्णों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। छात्र एवं नौजवान सोसल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको जोड़ने से हम अपने संदेश को समाज तक पहुंचा सकते हैं। मनुवादी मीडिया शायद ही हमारी बातों को छापती है, इसलिए सोसल मीडिया हमारे लिए जीवन रेखा का काम करेगी। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल एवं निर्भया का बलात्कार एवं हत्या के आंदोलन को सोसल मीडिया ने ही आगे बढ़ाया था। परिसंघ के सभी कार्यकर्त्ताओं व पदाधिकारियों की अब जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों और नौजवानों को जागरूक करें और उनमें से जो नेतृत्व उभरे उसका नाम, पता, फोन, ईमेल हमारे पास फौरन एस.एम.एस. या ईमेल द्वारा भेजें। यदि ईमेल करने में असुविधा हो तो पत्र के माध्यम से हमें सूचित करें। म0प्र0, उ0प्र0, दिल्ली एवं हरियाणा के छात्रों एवं नौजवानों को संगठित करने का काम शुरू हो गया है। इस समाज को गर्त में जाने से कौन बचा सकता है कि जिसके लिए हम लड़ाई लड़ें वह संवेदित ही न हो सके। परिस्थिति तो ऐसी बन गयी है कि अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों एवं नौजवानों को सड़कों पर आ जाना चाहिए, क्योंकि निजीकरण की वजह से इन्हीं की सबसे अधिक हानि है। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं तो पढ़ाई-लिखाई का क्या मतलब ?अब ज्यादातर नौकरियां निजी क्षेत्र में पैदा हो रही हैं, जहां हमे अवसर नहीं मिलेगा इसलिए कि ज्यादातर बातें यहां पर जाति के आधार पर तय होती हैं।

निजी क्षेत्र के लिए हम एक तरफ संघर्ष करते रहें लेकिन दूसरी तरफ व्यापार एवं व्यवसाय के लिए अपने को तैयार करें। हमारे समाज में लघु एवं छोटे स्तर के ही कारोबारी हैं और बहुत ही बिरले मध्यम स्तर तक पहुंच सके हैं। बड़े स्तर के व्यापारी देश में दो-चार ही हो सकते हैं। धन-सम्पत्ति कमाने का संबंध शिक्षा से बहुत नहीं है, क्योंकि बनिया ज्यादा पढ़ा-लिखा न होकर व्यापार एवं उद्योग में सफल है। सामाजिक आंदोलन तो बहुत पहले से चलाया जाता रहा है, लेकिन आर्थिक आंदोलन अभी तक नहीं चला है। कुछ लोगों ने मनुवादी पूंजीपतियों की तर्ज पर दलितों एवं आदिवासियों का व्यापारिक संगठन बनाया है और मीडिया के सामने इसे इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे समाज में भी पूंजीपति पैदा हो गए हैं। कई बार पत्रकारों ने हमसे पूछा कि अब आपको निजी क्षेत्र में आरक्षण की क्या आवश्यकता है, जब दलित, आदिवासी भी पूंजीपति हो गए हैं ?उस समय बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना, क्योंकि हमारे ही लोग मनुवादी पूंजीपतियों के आशीर्वाद से ढिंढोरा पीट रहे हैं कि अब दलित, आदिवासी भी पूंजीपति हो गए हैं। इन्हें देश के बड़े पूंजीपति जैसे - टाटा, गोदरेज, अनु आगा आदि का आशिर्वाद मिल गया है। ये सरकार से मिलकर उसकी मदद करने के लिए कहते हैं, जैसे मनुवादी पूंजपीतियों के संगठन और यह भी कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं चाहिए। मनुवादी पूंजीपति एवं सरकार की साजिश है कि निजी क्षेत्र में हमारी आरक्षण की लड़ाई को कमजोर किया जाए। इनसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने आरक्षण खत्म करने की मांग उठायी है। इस तरह से न केवल मनुवादियों की ओर से दलित समाज को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हमारे लोग भी इसमें शामिल हैं। आरक्षण हमारी जीवन रेखा है। आरक्षण के द्वारा की गयी प्रगति को हम अगर निकाल दें तो वहीं खड़े मिलते हैं, जहां आजादी के पहले थे। आप लोगों को सलाह दी जा रही है कि जहां तक संभव हो, दलित-आदिवासी व्यापारियों से सम्पर्क करें, उन्हें संगठित करें तथा उनका नाम, पता, ईमेल, फोन इत्यादि जिस तरह से छात्रों एवं नौजवानों का मांगा गया है, उसी तरह से इसका भी भेजें। यदि हर स्तर पर धरना-प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ तो उपरोक्त मांगें पूरी होने वाली नहीं हैं।

सद्भावनाओं सहित,

आपका,

Udit Raj

(उदित राज)

इंजपा की पश्चिमी चंपारण जिला इकाई गठित

गत् 3 फरवरी, 2013 को पश्चिमी चंपारण में इंडियन जस्टिस पार्टी की बैठक भागीरथी राम, प्रदेश उपमहासचिव के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस बैठक में सुधीर कुमार को जिलाध्यक्ष, केदारनाथ राम को प्रखंड अध्यक्ष, गौनहा, सुमित्रा देवी को जमुआ पंचायत अध्यक्ष-महिला मोर्चा, मनोज पासवान को प्रखंड अध्यक्ष, नरकटिया गंज और विनोद कुमार जायसवाल को प्रखंड सचिव, नरकटिया गंज के पद पर नियुक्त किया गया।

इस बर्बरता का एक इलाज: डाइवर्सिटी

एच. एल. दुसाध

मित्रों प्रायः 36 घंटे बाद फेसबुक खोला तो शोषित समाज दल द्वारा पटना विश्वविद्यालय के आंबेडकर छात्रावास में सवर्णों (भूमिहारों) के तांडव के तस्वीर देखकर आँखें भर आईं और गर्दन शर्म से झुक गई अपनी बेबसी पर। तस्वीर देखकर व्यक्ति दुसाध के दिल में लाखों अत्मसम्मानीय दलितों की भांति तो तात्क्षणिक प्रतिक्रिया यह हुई कि इस धरा को सवर्णविहीन कर दिया जाय। पर खुद को संभालने के बाद लेखक दुसाध ने कहा, "क्या यह असंभव और अमानवीय कार्य नहीं होगा? पर, मित्रों इस समय बात मानवीयता की करूं तो बनावटी ही लगेगी। सच्ची बात तो यह है कि लेखक दुसाध पर व्यक्ति दुसाध हावी है। पर सच्चाई यह है कि हम विविध कारणों से धरती को सवर्णविहीन नहीं कर सकते। ऐसे में भूमिहारों के अत्याचार का शिकार बने दलित छात्रों और उनके अभिभावकों को मेरा यही सुझाव है कि ऐसी घटनाओं के बाद पूरे देश के दलित जो करते हैं, वही करें अर्थात थाने में जाएँ और केस दर्ज करें। हालाँकि मैं जानता हूँ इससे बहुत कुछ होना–जाना नहीं है। पर, आपको संतोष तो रहेगा कि जो हथियार देश के संविधान ने सुलभ कराया उसका इस्लेमाल तो किया। पर, यदि इसका स्थाई समाधान चाहते हैं, हालाँकि यह बताने का इस समय उपयुक्त समय नहीं है, तो भी मेरे असमय सुझाव पर गौर करें।

पहला, सवर्णों के हित में पूरी तरह क्रियाशील नीतीश सरकार ने मंडल–उत्तरकाल में सवर्णों के लिए सबसे बड़े आतंक बहुजन–एकता को ध्वस्त करने की साजिश के तहत तरह–तरह के जो जाल बिछाए हैं, जिनमें एक दलित–महादलित का फंदा भी है, उससे उबरें। सवर्णों ने हॉस्टल में बर्बरता को अंजाम देते समय सबको दलित मानकर ही अत्याचार किया है, महादलितों पर रहम किया, ऐसा मुझे नहीं लगता।

दूसरा, बाबा साहेब ने सवर्णों द्वारा किये जा रहे अत्याचार के पीछे बहुत से कारणों को गिनाया है पर जो खास बात बताया है, वह यह कि ऐसा करने में सफल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके शस्त्रागार का मुख्य हथियार आर्थिक शक्ति है।

तो मित्रों आज भावावेश में आकर यदि भूमिहारों कि भाषा में ही जवाब देते हैं तो शायद आपको तात्कालिक सुख यह मिल जाय कि आपने उनसे बदला ले लिया। पर, यह कोई सही समाधान हुआ? वास्तविक समाधान तो तभी होगा जब उनके शस्त्रागार का मुख्य हथियार, आर्थिक शक्ति कमजोर कर दें और इसके लिए आपके पास एक ही हथियार है और वह है डाइवर्सिटी। मित्रों इस किस्म की घटनाएं रह–रह कर होती रही है और दूसरे बहुजन बुद्धिजीवियों कि तरह मैं भी अपनी राय देता रहा हूँ। मेरी बराबर राय यही रही है कि भारत की हिंदी पट्टी मानव सभ्यता कि दौड़ में 600 साल पीछे है। यहाँ वर्ण–व्यवस्था द्वारा शक्ति संपन्न बने लोगों में, चाहे वह लेखक–पत्रकार–जज ही क्यों न हो, 'जियो और जीने' दो की भावना नहीं है। वे सभी बर्बर और सख्त के भक्त हैं। ऐसे लोगों का एक ही इलाज़ है वह यह कि वर्ण–व्यवस्था के वंचितों को शक्ति से लैश किया जाय और ऐसा करने का एक ही उपाय है डाइवर्सिटी।

आपको बता दूं कि भारत के मुट्ठी बार सवर्ण जिस तरह शक्ति के स्त्रोतों (आर्थिक–राजनीति–धार्मिक) पर 80.90 प्रतिशत कब्ज़ा जमाए बैठे हैं, ठीक वही स्थिति दक्षिण अफ्रीका में गोरों ने कर रखी थी। वहां 9 प्रतिशत गोरों ने शक्ति के सभी स्त्रोतों पर 80.90 प्रतिशत कब्ज़ा जमा रखा था। किन्तु मंडेला के सत्ता में आने के बाद जब डाइवर्सिटी अर्थात जिसकी जितनी संख्या भारी–उसकी उतनी भागीदारी लागू हुई तो आज गोरे अफ्रीका छोड़कर दूसरे देशों में पनाह ले रहे हैं। अफ्रीका की तरह यहाँ भी अगर हर क्षेत्र में जिसकी जितनी संख्या...लागू हो गई उस दिन सवर्ण दक्षिण अफ्रीका के गोरों की भांति भले ही भारत छोड़कर न भागे किन्तु अपनी औकात पर आ जायेंगे। फिर दलित–आदिवासी–पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से युक्त बहुजन समाज पर जुल्म ढाने की हिमाकत नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ सवर्णों को दुरुस्त करने दलित–पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के हको–हुकूक को स्थापित करने के लिए डाइवर्सिटी से बेहतर हथियार नहीं हो सकता। सवर्णो के जुल्मो–सितम को भूलकर बहुजनों को अपनी अधिकतकतम ऊर्जा उस हथियार को खोज में लगानी चाहिए जिससे बहुजनो को ताकतवर बनाया जा सके। बहुजन समाज के लतियाये जाने का बड़ा कारण यह है कि यह सिर्फ रोता–गाता रहा है, पर समस्यायों के निदान का सटिक सूत्र ढूँढने में ऊर्जा नहीं खपाया।... आज मैं पुनः यही कहूँगा कि पटना में भूमिहारों द्वारा किए गए अत्याचार को भूलकर अपनी सारी ताकत उनके प्रतिकार का सही हथियार तलाशने में लगाओ। मैं कहता हूँ सर्वोत्तम हथियार डाइवर्सिटी है। इसे लागू कर ही उनकी स्थिति दक्षिण अफ्रीका के गोरो जैसी बनाई जा सकती है। आपके पास क्या इसका उपाय है?

6 अप्रैल को बाल संग्रहालय मैदान, चारबाग, लखनऊ में

विशाल रैली

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, पासव महासंघ व अन्य के नेतृत्व में पदोन्नति एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए 6 अप्रैल, 2013 को प्रातः 10 बजे बाल संग्रहालय, चारबाग, लखनऊ में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली को मुख्य रूप से डॉ0 उदित राज जी सम्बोधित करेंगें। आप सभी से निवेदन है अपने अधिकारों को सुरक्षित कराने एवं समतामूलक भारत के निर्माण हेतु साथियों सहित पहुंचकर रैली को सफल बनाएं।

कौशल किशोर
पूर्व श्रममंत्री,
रा. अध्यक्ष, पा. महासंघ
9415005536

पी.सी. कुरील
राष्ट्रीय संयोजक,
रा. भागीदारी आन्दोलन
9415024510

भवन नाथ पासवान
प्रदेश अध्यक्ष
अजा/जजा परिसंघ
9415158866

इंडियन जस्टिस पार्टी का एकदिवसीय धरना

डॉ. राम उदय शर्मा

बिहार। गत् 6 फरवरी को बेगूसराय में भूमिहीनों को चार डेसीमल जमीन देने, समान व अनिवार्य शिक्षा लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर इंडियन जस्टिस पार्टी ने समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। धरना का अध्यक्षता करते हुए पार्टी के राम उदय शर्मा का कहना था कि बिहार में सबसे बड़ी विडंबना है कि जो खेती–मजदूरी करता है उसके पास अपना रहने तक का जमीन नहीं होता। आर्थिक जगत में उनकी भागीदारी नहीं के बराबर है। निजीकरण एवं उदारीकरण के वजह से पैसे एवं पूंजीपति का महत्व बढ़ गया है। पूंजीवादी इतने ताकतवर हो गए हैं कि सभी जगह रूपये के बल पर भूमि को खरीद रहे हैं। गरीब मजदूर गंदे नाला, सड़क किनारे अपना झोपड़ी डाल कर रहने पर मजबूर हैं। वहां भी पूंजीवादी के इशारे पर पदाधिकारी भूमि अतिक्रमण बताकर झोपड़ी उजार फेंकते हैं। कितनी दुःख–दर्द की बात है। इस समस्या पर किसी दल को दर्द नहीं है और ना ही चिंता। क्या हम गरीब इस समाज का अंग नहीं हैं? अगर हम गरीब इस समाज का अंग हैं तो हमें सम्मान की जिन्दगी जीने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। क्या हम भूमिहीनों के लिए सरकार भूमि व्यवस्था नहीं करा सकती है। अगर हम गरीब भूमिहीन को 4 डेसीमल भूमि सरकार नहीं देगी तो हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे। भूमिहीन कोई जाति नहीं है। भूमि पर रहने का अधिकार सभी का है। इसलिए हम सभी भूमिहीन को सरकार जमीन उपलब्ध कराये। भूमि सुधार कानून लागू नहीं होने के कारण गरीब और अमीर के बीच दूरी बढ़ा। भूस्वामी के अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया और जितनी जमीन का अधिग्रहण भी किया गया, उसे भूमिहीनों में बंटवारा नहीं किया गया। जिसके कारण गरीब और अमीर के बीच की खाई दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। इंडियन जस्टिस पार्टी सरकार से मांग करती है कि जो वास्तविक भूमिहीन हैं उन्हें रहने के लिए आवास हेतु अतिशीघ्र कम से कम 4 डेसीमल जमीन का हस्तांतरण आज के दौर में अति आवश्यक हो गया है। दलित–पिछड़ा, अतिपिछड़ा एवं अन्य भूमिहीन को अपना झोपड़ी डालने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अगर भूमिहीन गरीब को सामूहिक रूप से उत्थान करना है तो सबसे पहले आवास भूमि 4 डेसीमल देना सुनिश्चित करे। समान एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करे जो शिक्षा प्रधानमंत्री व बड़े अधिकारियों के बच्चों को मिले वहीं आम नागरिक को भी मिलें।

धरना के माध्यम से निम्नलिखित मांग की गई :–

1. भूमिहीन परिवार को 4 डेसीमल भूमि देना सुनिश्चित करें,

2. समान एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करें,

3. समस्तीपुर पंचायत (सा. कमाल) बेगूसराय खरागैर मजरूआ का प्रश्नगत भूमि का विवरण इस प्रकार है :

मौजा : समस्तीपुर, थाना संख्या : 661, खसरा : 612, तौजी : 756, खाता : 197, रकवा : 2–3–6–0 पर बसे भूमिहीनों को आवास पर्चा निर्गत करें। भूमिहीनों की सूची निम्न प्रकार करें–

1. सुमित्रा देवी पति स्व. जगदीश शर्मा, 2. कापो महतो पति मातो महता, 3. उमेश पटेल पति स्व. जगदीश शर्मा, 4. उमेश पटेल पिता स्व. जगदीश पटेल, 5. साधुशरण महतो पिता जगदीश महतो, 6. नबल महतो पिता जगदीश महतो, 7. नबल महतो पिता जगदीश महतो, 8. राम महतो, 9. रामजी साह पिता स्व. भोला साह, 10. भुषण साह पिता स्व. नुनु साह, 11. लक्ष्मण साह पिता स्व. भोला साह, 12. रामचन्द्र पंडित पिता स्व. भकोल पंडित, 13. दर्शन साह पिता स्व. कलेश्वर साह 14. हरदेव राय पिता उमाशंकर महतो एवं अमरजीत राय पिता जयजय राम महतो वगैरह सुयोग्य श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 के भूमिहीन परिवार लगभग 50–60 वर्षों से बुद्दवास कर रहे हैं। इन सभी को प्रश्नगत भूमि पर बसे भूमिहीन को आवास पर्चा निर्गत करें।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

<u>सहयोग राशि:</u>

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

बलात्कार की जड़ें हिन्दू संस्कृति में

महिला अत्याचार भारतीय समाज की रोजमर्रा की सच्चाई है। यह भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है जो बेखौफ होकर निरंतर जारी है। दिल्ली गैंगरेप कोई अपवाद घटना नहीं है।

मुख्तयार सिंह

निश्चित तौर पर जिस युवती ने अपने मासिक धर्म के बाद वस्त्र बदल लिए हैं वह पवित्र है। अतः जब युवती अपने मासिक धर्म के बाद वस्त्र बदल लें जब उस उत्कृष्ठ महिला को सहवास के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। अगर वह राजी न हो तो उसे प्रलोभन दो। अगर वह फिर भी न माने तो लाठी से उसकी पिटाई लगाओ या उसे घूंसे मारो और यह कहते हुए उसे काबू में कर लो कि –मैं अपने पौरुष और तेज से तुम्हारी सुषमा ले रहा हूँ । (बृहदारण्यकपनिषद! 6.4.9.21)

गत् 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की शिकार की लड़की का मामला सड़क से संसद तक जोर–शोर से गूंजा और पूरी दुनिया में अखबारों की सुर्खियां बना। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, अभिनेत्री व सांसद जया बच्चन से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा तक अनेकानेक लोगों ने आंसू बहाए। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बेटी के पिता होने का हवाला दिया। मीडिया, कारपोरेट समूहों और फिल्मी दुनिया में भारी संवेदनशीलता जताई। बलात्कार पर संवेदनशीलता, दुःख व रोष भी जताया जाना चाहिए। किन्तु आखिर सारी संवेदनशीलता एक ही बलात्कार तक सीमित क्यों?

विगत वर्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंतर–मंतर व राजघाट पर विशाल प्रदर्शन हुए, जिन्हें मीडिया ने और बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया। एक भीड़ इकट्ठी हुई कि भ्रष्टाचार को समाप्त होना चाहिए। बस जमावड़ा लग गया। इस बात पर विचार किए बिना कि भ्रष्टाचार क्या है, कौन करता है और कैसे समाप्त होगा? बिना इस पर विचार किए भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो गई और इसे पवित्र मुद्दे के रूप में पेश किया गया। यह प्रश्न गायब थे कि वह व्यक्ति कौन है जो भ्रष्टाचार कर रहा है और किस तरह से भ्रष्टाचार को समर्थन मिल रहा है। और जो इन प्रश्नों को उठाए तो उसे उस फासीवादी वातावरण में भ्रष्टाचार के विरूद्ध पवित्र जंग में बाधा डालने वाला कहा गया।

इस बार भी स्वतः स्फूर्त भीड़ इकट्ठा हुई कि बलात्कार पीड़ित को न्याय मिलनी चाहिए। हां, बिल्कुल मिलनी चाहिए। किन्तु केवल इसी को क्यों, बांकि को क्यों नहीं? सांप्रदायिक दंगो में जिन महिलाओं के पेट में तलवार भोंकी गई हैं, वे आज भी न्याय के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। जाति के आधार पर अत्याचार–खैरलांजी, महाराष्ट्र (2006) से लेकर हाल में हरियाणा के बलात्कार की लंबी श्रृंखला–क्या बलात्कार की परिभाषा में नहीं आते?

महिला अत्याचार भारतीय समाज की रोजमर्रा की सच्चाई है। यह भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है जो बेखौफ होकर निरंतर जारी है। यह कभी–कभी प्रकट होकर सामने आता है और अक्सर दबा दिया जाता है। दिल्ली गैंगरेप कोई अपवाद घटना नहीं है। भारतीय समाज में जो रेप की घटनाएं होती हैं, उनमें से अधिकांशतः न तो बलात्कारी पुरुष की विकृत मानसिकता का परिणाम है और न सेक्सुअल इच्छा को पूरा करने की होते हैं। बल्कि भारत में रेप किसी वर्ग विशेष की आवाज दबाने और खौफ पैदा करने का एक यंत्र रहा है।

क्या कारण है कि सोनी शौरी के मसले पर जिस अंकित गर्ग को जेल की सलाखों में होना चाहिए वो राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। क्या ऐसा नहीं है कि जो रेप प्रभु वर्ग और उसका साथ देने वाली व्यवस्था की मर्जी के बिना होता है, चिल्लपो उन्हीं पर होती है बांकि पर नहीं। जिस रेप की आवाज को प्रभु वर्ग और उसका साथ देने वाली व्यवस्था उठाना चाहती है, उठा लेती है और जिस आवाज को दबाना चाहती है, दबा देती है।

मात्र मामला रेप का नहीं, मामला पूरे भारतीय समाज की शक्ति सिद्धांतों पर आधारित सामंतवादी जातिवादी संरचना का है। दलित आदिवासी महिला मात्र पितृसत्ता के तहत पुरुषों का ही शिकार नहीं होती, उसे महिलाओं का भी शिकार बनना पड़ता है। जब भंवरी देवी के मसले पर माननीय न्यायालय ने न्याय सुनाया था कि कोई अपर कास्ट पुरुष लोअर कास्ट की महिला से रेप नहीं कर सकता और अभियुक्तों को बरी घोषित किया था तो अपर कास्ट महिलाओं ने अभियुक्तों की जीत के पक्ष में जुलूस निकाले थे। शर्म है ऐसे माननीय न्यायाधीश पर!

लक्ष्मीओरंग का मामला कोई बहुत अलग नहीं है। लक्ष्मीओरंग ने अपने बयान में कहा था कि सरकार और मीडिया ने मुझे मात्र इसलिए नजरंदाज किया, क्योंक मैं आदिवासी हूं। वर्तमाना घटना पर भी सरकार मीडिया का रोल छिपा नहीं है। मीडिया ने दिल्ली गैंग रेप को जोर–शोर से उठाया। क्यों लड़की को बताया गया कि यह ओबीसी, कुर्मी जाति समुदाय की (द हिन्दू समाचारपत्र, 20 दिसंबर, 2012) लड़की की मौत के बाद उसके पिता ने उजागर किया कि लड़की का नाम निर्भया पांडे है। क्या कारण था कि मीडिया ने बलात्कार पीड़ित की जाति की पड़ताल नहीं करवाई? क्या जाति भारत की एक अकाट्य सच्चाई नहीं है?

महिला अत्याचार भारतीय समाज की रोजमर्रा की सच्चाई है। यह भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा है जो बेखौफ होकर निरंतर जारी है। यह कभी–कभी प्रकट होकर सामने आता है और अक्सर दबा दिया जाता है। दिल्ली गैंगरेप कोई अपवाद घटना नहीं है। भारतीय समाज में जो रेप की घटनाएं होती हैं, उनमें से अधिकांशतः न तो बलात्कारी पुरुष की विकृत मानसिकता का परिणाम है और न सेक्सुअल इच्छा को पूरा करने की होते हैं। बल्कि भारत में रेप किसी वर्ग विशेष की आवाज दबाने और खौफ पैदा करने का एक यंत्र रहा है।

मुद्दा सामाजिक व्यवस्था और मानसिकता में परिवर्तन करने का है। कोई एक नियम, कानून या सजा रेप को दूर नहीं कर सकता, वह चाहे फांसी की सजा हो या केमिकल कस्ट्रेशन। यदि कोई ऐसा कह रहा है तो वह सामाजिक सच्चाई की कटुता से परिचित नहीं है या जानबूझ करा ध्यान भटकाना चाहता है। मामला कहीं अधिक गहरा है। महिला अत्याचार और जुल्म सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में बसा हुआ है और उसे शक्ति मिल रही है धर्म, संस्कृति और परंपराओं से। उस शक्ति संरचना और उसे पोषित करने वाले धर्म, संस्कृति पर चोट क्यों नहीं? हिन्दू पुराणों और अन्य ग्रंथों के अनुसार, ब्रह्म ने अपनी बेटी से रेप किया और उसे अपनी पत्नी बनाया। विष्णु ने अनुसूया और शिव ने मोहिनी के साथ रेप किया। इनको अपराधी घोषित नहीं किया गया।, बल्कि देवता घोषित किया गया। इन्हें देवता इसलिए बनाया गया कि पितृसत्ता और बलात्कारी मानसिकता को कोई चुनौती नहीं दे सके। मनुष्य के खिलाफ तो कोई बोल सकता है, देवताओं पर प्रश्न उठाना तो अधर्म है। आखिर उस पर चुप्पी कैसी?

महिलाओं को दोयम दर्जे का मनुष्य मनुस्मृति से लेकर रामचरितमानस तक बताया गया। वो सभी मूल्य, धारणाएं और परंपराएं ठुकराई जानी चाहिए जो पुरुष की तुलना में महिला को दोयम दर्जे का बनाते हैं। धर्मराज और सत्यवादी कहे जाने वाले युधिष्ठिर के लिए द्रोपदी तो वस्तु हैं जिसे उन्होंने जुए में लगा दिया। सीता को आदर्श महिला मात्र इसलिए माना जाता है, क्योंकि वह पुरुषों की, राम और लक्ष्मण की–कथित तौर पर आज्ञाकारी थी। क्या आज्ञाकारी होना ही आदर्श महिला का गुण है? नाक, कान कटवा कर सूपर्णखा न्याय के लिए भटक रही है। इन सभी मूल्यों को ठुकराए बिना महिलाओं के पक्ष में कोई परिवर्तन संभव नहीं है।

पितृसत्तात्मक और जातिगत शोषणकारी और भेदभावकारी स्वरूप पग–पग पर सामने आता है। फूलन देवी जिसके साथ अपर कास्ट के 15 लोगों ने गैंगरेप किया परंतु उसने पलटवार किया कि वह एक बहादूर महिला थी, क्यों मुंह मोड़ा जाता है फूलन देवी के नाम से? भारतीय महिलावादी आंदोलन सीमोन द बोउवार, केथ मिलेट और लुडविग फायरएस्टोन का नाम तो ले लेते हैं किन्तु फूलन देवी का क्यों नहीं?वह भी तब जब पिछले दिनों प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने फूलन देवी को विश्व स्तर की विद्रोही महिला का दर्जा दिया है?

दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के विरोध में अरविंद केजरीवाल व कुछ अन्य सिविल सोसायटियों ने 3 जनवरी को काला दिवस घोषित किया और दिल्ली के जंतर–मंतर पर सभा आयोजित की। वह दिन तो स्वागतयोग्य है ताकि न्यायिक प्रणाली अपना काम करे और अपराधियों को सजा मिल सके। आखिर यह काला दिवस कैसे हो गया? अगर काला दिवस मनाना ही था तो इसे 16 दिसंबर को घोषित किया जाना चाहिए था, जिस रात को सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना हुई थी। वास्तव में इस घोषणा के पीछे एक काला एजेंडा छुपा हुआ था। यह एजेंडा था–बहुजन समाज के गौरवपूर्ण दिवस को काला दिवस में बदलना। याद रहे कि 3 जनवरी को देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस है। इस दिन को भारत के कई समुदाय और विभिन्न लोग प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।

बहरहाल, दलित युवा लेखिका अनिता भारती ने 3 जनवरी को जंतर–मंतर पर ही एक सभा का आयोजन कर 3 जनवरी को काला दिवस घोषित किए जाने का पुरजोर विरोध कर इस साजिश को विफल कर दिया।

भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में बताया जाए कि पवित्र मानी जाने वाली संस्था सर्वाधिक अलोकतांत्रिक है। यह एक ऐसी संस्था है जिसमें वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीश अपर कास्ट पुरुष तो हैं ही, वे धनी वर्ग से भी हैं जो पितृसत्ता व जातिवादी मानसिकता से परिपूर्ण है। कई निर्णयों में ऐसा स्पष्ट हो चुका है। न्यायपालिका 'न्याय' नहीं सुनाती बल्कि 'निर्णय' सुनाती है। यह मात्र संयोग नहीं है कि जेल में बंद अधिकांश अभियुक्त दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। बिहार के जेल में बंद मौत की सजा पाए 36 में से 35 लोग दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। (देखें, प्रभात कुमार का शांडिल्य का सर्वे आधारित लेख, हंस) भारत सरकार के सचिव पद पर बैठे सभी लोग 'अपर कास्ट' के हैं और जेल में बंद अभियुक्त वंचित समाज के? अपराध के कारणों और उसकी व्याख्या नए सिरे से करने की जरूरत है। विवेचना करने की जरूरत है कि समाज के कमजोर तबकों की महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं होते, इन अपराधियों को क्यों सजा नहीं मिलती और कौन से कारण जिम्मेदार हैं इसके लिए?

बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने के बदले समाज को अपनी आत्मा को खंगालने की जरूरत है कि हमारे समाज को रुग्न करने वाली जड़े कहां हैं। उसे यह भी देखना होगा कि हमारी महिलाओं और लड़कियों से कैसे सलूक किया जाता है। हमें समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा, अन्यथा आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती।

Dalits and Obc are defamed in any case

Dr. Udit Raj

When a Dalit or Backward does an act, it is deemed to be detestable, defamatory and derogatory. These yardsticks have been determined by the uppercaste people. Whatever norms, professions or jobs which suit the convenience of the upper caste people, are deemed superior and honourable and whatever is beyond their capacity or capability, it is considered anti-religious, dirty and below their dignity. This has been their mind-set for centuries. First of all, when Dalits and Backwards were predominantly involved in Dance, Music, Drama and Painting, these activities were considered inferior.The practitioners of these arts were called dancers, singers, balladeers, drum beaters, etc. in a bad sense and was considered against the tenets of Hindu Dharma. Artists were treated like beggars but with the development or urban civilization, these activities became the prerogatives of the upper caste people. So much so that the upper caste people claimed these activities to be their original domain and claimed credit for the same at the international levl. Now for imparting training in these arts, institutions, cultural centres and Academies are being set up in big cities over which the upper caste people have got complete control. Shudra Devdasis are even today looked down upon but the fact is that it is precisely these Devdasis who have protected the arts of music and dance. Times have changed and through the medium of films, dance and music have become very popular. The famous Rajasthani dance of Kalbalia dance earned international laurels but now this art is also being grabbed by upper caste ladies and it has become an honourable profession. At one point of time, Dalits and Adivasis used to sing and dance in the open-air chaupals of villages and were called balladeers, dancers and but for the same art, now national competitions are held on TV. Dalits of Rajasthan have been singing the Nimbooda-Nimbooda folk songs for years but nobody bothered. When Aishwarya Rai sang this song in a movie, its popularity suddenly jups manifold.

After Independence, for nearly three decades, participation of Dalits in political governance remained very negligible.If due to reservation, Dalits and Adivasis got elected, most of them were politically dumb and deaf. Teachers in schools were often found to tell the students that they should emulate Chacha Nehru when they become adults. Circumstances have changed with the passage of time and power has come into the hands of backwards in most of the States and now politics has been branded as a dirty profession. Share of Dalits and backwards in Government has increased due to reservation, then they are being condemned as corrupt and inefficient. Voices are raised from different quarters that government departments are corrupt and inefficient and privatization is the only way out. The upper caste people will again gain sway due to privatization. Due to privatization of education, upper caste people have established their supremacy in this field. In today's context, private education is the big source of income but why is this trend not condemned. Before Independence, when the upper caste people were dominating in Govt. jobs, why they were not called traitors.

Immedately after Independence, the administration of the country has been in the hands of upper caste people because of which the social, political and economic foundations of the country were laid by them only. Corruption does not flourish in just a few months rather it takes a few decades to take its roots. Undoubtedly economic corruption has increased tremendously but for this the present day politicians and bureaucrats are not so much responsible as the politicians and bureaucrats of the early period of our Independence. It is not difficult to understand that the strength of the walls and roofs of a house are as strong as the foundations of that house. Even if we take the statement of Ashish Nandi, this contention does not prove true. He said that now Dalits, Backwards and Adivasis are becoming more corrupt. This statement of course, is not correct because the foundations of corruption were not laid by Dalits and Adivasis and even today they lag far behind the upper caste people in this area.

(This article has been published in Hindi newspaper NavBharat Times , dated- 9 February,2013.)

The caste club

Jaideep Mazumdar

Sociologist Ashis Nandy's controversial words at the Jaipur lit fest are being debated heatedly but there is one thing that is difficult to argue with: there is a lack of representation from the backward classes and tribals in the upper echelons of power in West Bengal. Over the last 100 years, he said, "nobody from the other backward classes (OBCs), the backward classes, the scheduled castes and scheduled tribes have (sic) come anywhere near power in West Bengal".

All the chief ministers of West Bengal and almost all their cabinet colleagues hailed from the upper castes.The representation of backward classes, castes and tribals in all the successive council of ministers - the Congress regimes and three short-lived coalitions from 1947 to 1977, the Left Front till 2011 and the Trinamool Congress now - has been merely token. In none of the governments was anyone from the backward sections or a tribal given a significant portfolio. And this in a state that not only cradled social reforms, but also one where people belonging to the scheduled castes, OBCs and scheduled tribes form nearly 68 per cent of the states population.

A look at the council of ministers from the time of the state's first chief minister, Dr Prafulla Chandra Ghosh, to Mamata Banerjee, proves Nandy right. What's more, though Brahmins form just two per cent of the state's population, they have held most of the important portfolios in successive regimes. Of the 44 ministers in Bengal now, as many as 14, including the chief minister, are Brahmins. Only two ministers are tribals and seven are from the scheduled castes and OBCs, most of them junior ministers. Tellingly, the most prominent among them - former CBI joint director Upen Biswas - is in charge of the backward classes welfare department. Others are in charge of departments like youth services and waterways. Forest is the only one of any significance held by an OBC minister.

Muslims, who form more than 25 per cent of the state's population, have only five representatives in the 44-member council of ministers. This has been the pattern in all successive ministries, including those during the Left's 34-year rule in Bengal.

"Brahmins and the upper castes have always held the most important and powerful portfolios in this state, irrespective of the party or coalition in power. It is indeed a paradox, but a very shameful one, that a state which has produced such great social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda and Ishwar Chandra Vidyasagar continues to keep the SCs, STs, OBCs and

Rest on Page-7...

International Conference On The Impact Of Phule-Ambedkerite Ideology On Contemporary Global Literature Held From 18th to 20th January, 2013, At Nashik.

Indira Athawale

An international conference was arranged on 'The Impact of Phule-Ambedkerite Ideology on Contemporary Global Literature' at Nashik from 18th to 20th January, 2013, by Dr. Indira Athawale, National Secretary General and President of the Maharashtra Unit of the All India Confederation of SC/ST Organizations under the aegis of its National Chairman, Dr. Udit Raj. This International Conference was the first of its kind in India. Some of the eminent persons both from within and outside the country had taken part in this Conference were Dr. Vasudeo Gade, Vice-Chancellor, Pune University, Dr. M.S. Gosavi, Secretary, G.E. Society, Shri Vaharu Sonawani, Dr. Anannya Wajapey, Dr. Udit Raj, Dr. Pushpa Gavit, Dr. Chrisatopher Queens, Dr. David Blundel and Dr. Hui-ji Wang.

In his inaugural address as chief guest, Dr. Vasudeo Gade, Vice-Chancellor, Pune University, congratulated Dr. Indira Athawale for her initiative in organizing the event on a grand scale. He said that what is being written by the contemporary Dalit thinkerss, poets and writers is merely a repetition of the past and the need of the present time that they should focus more on the current issues, concerns, challenges, scientific temperament in literature to bring about radical change in the caste system in the country. The Conference was further dividided into five technical sessions over a period of three days.

Day I–18.2.2013– Technical Sessions I, II

The first session of the Conference dealt with a wide range of discussions on "The Concept of Broken Peopele Discourse in Phule-Ambedkarite Marginialized Literature". Thirteen scholarly research papers were received out of which eight papers were presented in this session. Dr. Christopher Queens, Dr. David Blundel and Dr. Hui-ji Wang delivered a talk on the different aspects of Phule-Ambedkarite ideology and movements and focused on the need to voice the voiceless in the societies where the foundation of religion is caste, class and gender based. This lively talk was followed by paper presentation by the participants with a focus on the concept of broken people and its projection in Phule-Ambedkarite literature. There was a consensus among the scholars that in the early Marathi literature written during the high tide of Brahmanism, there was no place for Dalits in this literature. The space that Dalits occupied outside the villages in real life did not find any place in the world of Brahminical Marathi literature.In this paper presentation session, the research scholars and teacher delegates shared the view that the broken people were not projected in the early Brahminical Marathi literature but the Ambedkarite writers projected the broken people as the protagonists of Phule-Ambedkarite literature and placed it before the world readers to show them the harsh realities of the outcaste life of the broken people which voiced their anger and agonies in literature with a view to inculcate human values for the betterment of entire humanity. The second session on "Phule-Ambedkarite Literature & Contemporary Society was chaired by a famous Marathi poet Vaharu Sonawane and coordinated by Dr. Anjali Gautam. In his speech, Shri Vaharu Sonawane focused on the life of Dalits and their culture. He said that Dalit literature which is largely influenced by Phule-Ambedkar Ideology has a great potential to change the caste set up and very face of the country. Afterwards, research papers were presented by participants. The thrust of these research papers was the past and future impact of Ambedkarite literature on Dalits with a view to emancipate them and bring them into the mainstream of social, economic and cultural structure of the Indian society so that India could become a superpower in the comity of nations.

Day Two – 19.2.2013 Session III

The third session on "Discourse of Literary Values & Human Values in Phule-Ambedkarite Literature" , was chaired by Dr. Anannya Wajapaey, an eminent international thinker. She mainly focused on the aesthetic and human values reflected in Phule-Ambedkarite Literature and are rooted in Buddhism. These values are different from the aesthetic and human values reflected in the mainstream literature. Afterwards, research papers were presented by research scholars from across the country. The focus of these papers was the universal human values of freedom, fraternity, equality and justice which is the essence of Phule-Ambedkarite literature with a view to create an ideal society for the entire population of the country. Another factor that emerged here was that there was an urgent need to judge Dalit literature by a new set of criteria, a separate aesthetic that involves social circumstances, affirmation of life, search for freedom and humanism. Session IV of day Two on the "Impact of Phule Ambedkarite Ideology on the contemporary global feminist literature" which was chaired by Dr. Pushpa Gavit and coordinated by Dr. Chitra Mhalas.Dr. Pushpa Gavit said that the writings of Dalit authors have been greatly influenced and inspired by Dr. Ambedkar, Jyotiba Phule and Savitribai Phule who were the pioneers of the female education in India. In one of her poems, Dr. Pushpa Gavit gave a message of women's freedom and equal rights. Adivasi poetry has also been inspired by Jyotiba Phule and Dr. B.R. Ambedkar ideology and continues to inspire the present generation which is a healthy trend. Afterwards, research papers were read by the participants on Phule-Ambedkar's ideology as a strong support and inspsiration for Dalit authors for women's emancipation, freedom and equality. In the end, Dr. Gavit said that instead of presenting what and how the ideologies had influenced Dalit writing, we must focus on the need as to how the society could be moulded for betterment. Asstt. Prof. G.S. Baviskar thanked the chair, the paper presenters and the participants of the session.

Day Three -20.2.2013 – Technical Session V

The last technical session on "Multi-lingual discourse in Phule-Ambedkarite Literature" was chaired by Shri Raja Dhale, a renowned Ambedkarite writer and ccordinated by Dr. Indira Athawale.He addressed different issues, in detail, concerning Dalit Literature and reviewed the course of Phule-Ambedkarite literature and movements.Eminent Dalit writer Shri Laxman Gaikwad and an equally famous Dalit critic and thinker, Shri Manohar Jadhav were present on this occasion.They focused on different aspects of Phule-Ambedkarite literature and stressed that there was an urgent need to see Phule-Ambedkarite literature from a new angle to re-establish humanity by annihilating the Chaturvarna Vyavastha and inculcating scientific temperament in the Indian masses on the pattern of Phule-Ambedkarite writers and poets. Afterwards, different papers were read out on the Phule-Ambedkarkatite literature written in many other regional languages in the country.

Dr. Udit Raj, a famous political thinker and an eminent leader in his own right, addressed the valedictory session as a chief guest and urged the gathering to focus on the impact of Phule-Ambedkar Ideology on the contemporary society both within and outside the country. He appealed to the Ambedkarite writers to address the issues and concerns relating to Dalits and other downtrodden section of the society in the context of globalization.

Dr. Uttam Sonkamble, Dr. Chitra Mhalas and Asstt Prof. G.S. Baviskar present reports of the five technical sessions. A vote of thanks was proposed by Dr. Indira Athawala, coordinator of the conference to Dr. Udit Raj, Dr. M.S. Gosavi, Prof. S.B. Pandit , Prof. B. Devrajah and Dr. Ram Kulkarna for their unstinted support in organizing the event so successfully.

All India Confederation of SC/ST Organisations Circular No.-77, which has been sent to all the office bearers, is being published verbatim. All are requested to read out this circular to others and distribute its photocopies to the concerned people.

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
All India Confederation of SC/ST Organisations

Dr. Udit Raj
National Chairman

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Tel: 011-23354841, 011-23354842, Fax: 011-23354842
Email: dr.uditraj@gmail.com, web.: www.scstconfederation.org

Circular - 77 Dated 9/02/2013

My Dear Friends,

After the Rally held on 26.11.2012, this is the first circular and much water has flown during this period. On the 18th December, 2012, Reservation in Promotions Bill was passed in the Rajya Sabha. Certainly, our rally had a positive impact on the passing of this Bill. When the Bill was tabled in the Lok Sabha on 19.12.2012, a copy of the Bill was torn into pieces on the floor of the House by a Dalit MP of the Samajwadi Party. The Samajwadi Party has a strength of just 22 Members of Parliament which is just not sufficient for adjournment of the House . The House was adjourned four times when the issue was finally adjourned till 20.12.2012. The Parliament session was to continue till 22.12.2012 but the House was adjourned on 20.12.2012 and it is not understood as to what was the big hurry for doing so. When voting was to take place in the Rajya Sabha on the FDI issue, the Government appeared to be losing majority on the issue, BSP came to the rescue of the Government. At that time, we tried to convey to Ms Mayawati that the passing of the 117th Constitutional Amendment is more important than FDI, otherwise the Government will not pass the Reservation in Promotion Bill even on some flimsy grounds. Had the Government shown even half the zeal and determination which had been shown in getting the FDI Bill passed, the 117th Constitution Amendment Bill would have been easily passed. We are also at fault on this issue to some extent that after the national rally, we remain lethargic throughout the year. We had made a grand beginning by asking for participation in all the spheres including reservation in the private sector but now we have to put in serious efforts to restore our old right of reservation in promotions. What a paradox of this society? It seems that we shall again be thrown into the throes of slavery.

The benefits of reservation in private sector will go to the young people and students but we have not so far been able to associate them with our mission. There are students hostels for SC/ST nearly in every district. If we are able to convey our message to these hostlers, then it will not be difficult to further strengthen our campaign. Once students or youths join any movement or campaign, it get momentum. Our employees and officers are somewhat hesitant to make full use of social media like computers, internet, facebook, tweeter, blog MMS, miss call etc. while the upper caste people of our generation have started making use of the social media. Students and youths are making full use of the social media and by associating them with our movement, we shall be able connect ourselves with the society. Manuvadi media is very reluctant to publish our views and under these circumstances the social media could become our lifeline. Campaigns of Anna Hazafde, Arvind Kejriwal and Nirbhaya Rape and Murder case gained widespread publicity because of the social media also. Thus, it is the bounden duty of all the workers and office bearers of the Confederation to create awareness among youths and students and if any leaders emerge from these groups, their names, addresses, phone numbers, emails etc. should be sent to us immediately through MMS or email. If any difficulty is experience in sending emails, this information could be given through letters. We have already started the job of organizing the students and youths of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi and Haryana. Who can save a community from going to the dogs for whom we launch a relentless struggle and they do not feel concerned about it. The situation has become desperate that it is high time that the SC/ST students and youths should come on the streets for their rights because they have been put to the greatest disadvantage because of privatization. Education does not have any meaning if there is no reservation in promotions. Now most of the vacancies are taking place where SC/ST youths will not get a chance because jobs in the private sector are determined on the basis of caste.

On the one hand, we should continue our struggle for reservation in the private sector and other hand, we should gird up our loins for entering the fields of commerce and industry. In our society, most of the businessmen are from small and micro sectors and there are very few from the middle sector. Businessmen from the corporate sector may be hardly two or three. Money earning is not very much related to education because despite little education, the Baniyas are quite successful in trade and industry. Social movement or campaign has been going on since long but an economic movement is yet to be launched. On the lines upper caste industrialists, a Dalit Chamber of Commerce and Industry has been constituted and projecting the same in the media as if a lot many capitalists from amongst Dalits have come into existence. On so many occasions, press correspondences have asked us as to why we are insisting on reservation in private sector when Dalits and Adivasis have also become Capitalists. At that time, it becomes difficult to counter them because of these people. These people have got the blessings of big capitalists like Tata, Godrej and Anu Agha etc. They tell the Government that what services they can offer liket like Manuvadi capitalist. These people are also propagating that Dalits and Adivasis do not need reservation in private sector. The Manuvadi capitalists and the Government are colluding with each other to weaken our struggle for reservation in the private sector. We should be very careful about these nefarious designs. Baba Sahib Dr. Ambedkar's grand son, Prakash Ambedkar, has raised a demand for abolition of reservation. Like this, not only Manuvadis are making desperate attempts to enslave Dalits again but our own people are also taking active part in this game-plan. Reservation is our life-line. If we exclude the progress made because of reservation, then we shall find ourselves at the same place where we were at the time of Independence. This is my earnest advice to you to please contact Dalit/Adivasi traders and businessmen, as much as possible, organize them and send us their names, addresses, emails, phones etc. just as we have asked for this information from students and youths. The immediate action is to launch agitation at each and every level.

With best wishes,

Yours Sincerely

Udit Raj

(Dr. Udit Raj)

... Rest of Page-5

The caste club

minorities out of power," says sociologist Madhusudhan Ghosh. In fact, he points out, Brahmins and upper castes outnumber SCs, STs, OBCs and minorities in the middle and upper bureaucracy, police force, various professions and even the academia in Bengal. And this was the case during the British rule as well: most of the members of the Bengal provincial assembly, right from 1892 when elections to the body first took place, were Brahmins and upper castes.

They upper caste made for nearly 75 per cent of the council of ministers under chief ministers Prafulla Chandra Ghosh, Bidhan Chandra Roy, Prafulla Chadra Sen, Ajoy Mukherjee and Siddhartha Shankar Ray till 1977 when the Left Front took over the reins of power. The first ministry under Jyoti Basu was slightly more egalitarian - the representation of the upper castes fell to about 60 per cent, but increased to 65 per cent and then 70 per cent during his second and third tenures respectively. His successor Buddhadeb Bhattacharjee kept this caste composition intact while forming his two ministries in 2001 and 2006. Mamata Banerjee too has lived up to the tradition.

Expectedly, the marginalised sections have started protesting. As senior IPS officer Nazrul Islam says, it is time for Bengal's SCs, STs, OBCs and Muslims to get together and launch a political battle. "We will then be the king-makers and the chief minister of the state will be a Muslim, SC or OBC," he says.

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 6 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 February, 2013

मादक पदार्थों से दूर रहें

-गौतम बुद्ध

SC/ST STUDENTS' STRONG DEMAND FOR RESERVATION IN PRIVATE SECTOR

Harshvardhan Dawane

Dalit/Adivasi students of Phule-Ambedkar Students Association (FASA) held a Conference at Nanded, Mahrashtra. The main speaker at the Conference was Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations. The conference was inaugurated by revolutionary poet 'Gadar' (Hyderabad) and was presided over by Dr. Indira Athawale.

Reservation in private sector is a question of life and death for Dalit and Adivasi students. Parents of Dalit and Adivasi students are spending their hard-earned money just to secure a bright future for their children.But because of privatization, future of Dalit and Adivasi students has become very bleak. Dr. Udit Raj has indeed very aptly said that if reservation in private is not granted, education of Dalit and Adivasi students is meaningless. Dr. Udit Raj that while in a country capitalist country like America there is affirmative action for blacks, in our country, Dalits and Adivasis are being discriminated and exploited in the private sector. It is, therefore, imperative for our Government to introduce reservation in the private sector. For the last ten years, the All India Confederation of SC/ST Organization has been fighting a relentless struggle for Dalit and Adivasi students but now the time has come when these students must take it upon themselves to fight for their cause. It was unanimously decided at the conference that in December, 2013, a massive rally will be organized in Delhi to press for their demand for reservation in private sector.

Conveying his message through his poetry and songs, revolutionary poet 'Gadar' (Hyderabad) said that reservation has been prevalent in our countries for centuries and it is because of this reservation that the uppercaste people continued to treat Dalits and Adivasis as untouchables and slaves by confining them to some of the most unhygienic jobs and low professions. But Dr. Ambedkar broke the shackles of this slavery through the medium of our Constitution by securing education, reservation in government jobs and politics for Dalits and Adivasis. The Manuvadi uppercaste capitalists of this country, however, are bent upon doing their best to ensure that the constitutional reservation is abolished and Dalits and Adivasis are again made slaves. It is, therefore, of utmost importance that Dalit/Adivasi students and youths should unite as a single powerful front and fight for reservation in private sector otherwise our future is dark.

> **Education of Dalits and Advasis without reservation in private sector is meaningless**
>
> **–Dr. Udit Raj**
> **National Chairman,**
> **All India Confederation**
> **of SC/ST Organisations**

While addressing the Dalit/Adivasi student community at the conference, the student leader Harshvardhan said that we have to launch powerful struggle for right to education, scholarship and hostel facilities for Dalit/Adivasi students. Now we have to become serious about our right for employment. Without reservation in the private sector, education for Dalit/Adivasi students is meaningless.For the last thousands of years, efforts are being made to give rights and participation in governance to Dalits and Adivasis but the upper caste people have been the biggest stumbling block in their way. Dalit/Adivasi students must, therefore, come forward to secure their share in governance. Government must concede their demand for reservation in different fields like Army, judiciary, films besides reservation in the private sector otherwise Dalits/Adivasis will raise a demand for "Dalistan" , a homeland for themselves. The audience loudly applauded Shri Harshvardhan for his views.

Dr. Indira Athawale, President of the Conference, said that as there is no national body for Dalit/Adivasi students, their problems have only escalated due to which they are exploited in universities. Marks are given keeping in view the caste of a student. For this purpose, a national Dalit/Adivasi Student Front is essential to voice their grievances effectively.

Shri Nitin Gaikwad, District President of Nanded, Shri Madhav Pandit, District President of Hingoli, Shri Nikhil Makrand, District President of Parbani, etc. and approximately three thousand students took part in thje deliberations of the Conference. They demanded reservation in private sector, armed forces, higher judiciary and scholarships in line with the price rise. When a consensus was sought from the audience on the issue of launching a strong campaign for free education for SC/ST students at the Tehsil and District level, reservation in private schools and colleges, the students and other participants raised their hands in unison in support of the demands

Dalit/Adivasi Student Conference was inaugurated by lighting a lamp for the launch of a revolutionary period. The organizer of the programme was Balaji Kodamandal.

Contribution of Rahul Sonale, Bandoo Narwade, Ravi Vaghmare, Manoj Jamnore, Nagorao Bhagyavant, Vishal Kamble, Rahul Sonkamble, Sahebrao Narwade, Dhamma Vadhwe,Sambhaji Gayakwad, Sandeep Kauthekar, Atul Vachchewar, Tukaram Pandilwad, Sumedh Chinchalwad, Nagesh Sonule was also gratefully acknowledged for successful completion of the Conference.

(From L to R)-People Welcoming Gadar, Dr. Udit Raj (Centre), Indira Athawale

A view of the huge gathering at the Conference

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

Computer typesetting by N. K. Karn